परिवार
सारांश वचन पत्र 2023

भोजन का अधिकार

- खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर सभी जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध करायेंगे।
- मां की रसोई संचालित कर गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करायेंगे।
- नये राशन कार्ड बनायेंगे।

आवास का अधिकार

- आवास का अधिकार सुनिश्चित करेंगे।
- आवासहीन परिवारों का पुनः सर्वे करायेंगे व ग्रामीण क्षेत्र में नई आबादी घोषित कर भू-खण्ड आवंटित करेंगे।
- पुश्तैनी आवासों एवं आवंटित आवासीय पट्टों की निःशुल्क रजिस्ट्री कर मालिकाना हक देंगे।
- "अपना परिवार, अपना आवास" उपलब्ध कराने की नीति बनायेंगे।
- 600 वर्ग फीट तक के आवास की रजिस्ट्री में 50% तक की छूट देंगे।
- राज्य शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना में दी जाने वाली सहायता राशि एक समान करेंगे।

स्वास्थ्य का अधिकार

- स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनायेंगे।
- वरदान स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ करेंगे। परिवारों का 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख तक दुर्घटना बीमा करायेंगे।
- सस्ती दवा, सुलभ दवा की नीति पर कार्य करते हुए "हमारी दवाई की दुकान" प्रारंभ करेंगे।
- सड़क दुर्घटना में गोल्डन आवर में उपचार मिले इस हेतु सहायता करने वाले नागरिक को वरदान स्वास्थ्य दूत प्रशंसा पत्र एवं 2 हजार रूपये की सम्मान निधि देंगे।
- सीनियर सिटीजन निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच योजना प्रारंभ करेंगे।
- अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिये अंगदान दाताओं का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार करायेंगे।
- चरक प्राकृतिक चिकित्सा आरोग्यधाम प्रमुख संभागीय मुख्यालयों पर स्थापित करेंगे एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलेंगे।

सस्ती-सुलभ बिजली का अधिकार

- 100 यूनिट घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे।
- 200 यूनिट घरेलू बिजली का बिल हाफ करेंगे।

खुशहाल परिवार खुशहाल मध्यप्रदेश

शिक्षा का अधिकार

- के.जी. से कक्षा 12वीं तक की उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है।
- पढ़ो-पढ़ाओ योजना प्रारंभ करेंगे। पात्र बच्चों को कक्षावार 500 रूपये से 1500 रूपये की सहायता प्रतिमाह उपलब्ध करायेंगे।
- सभी विधानसभा क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के "राज्य नवोदय विद्यालय" प्रारंभ करेंगे और संभागीय मुख्यालयों पर "राज्य सैनिक स्कूल" शुरू करेंगे।
- छात्रवृत्ति के भुगतान का अधिकार अधिनियम लागू करेंगे।
- उच्च शिक्षा को "शिक्षा सह-रोजगार केन्द्रित" बनायेंगे एवं रोजगारमूलक व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे।

स्वच्छ जल का अधिकार

- स्वच्छ पेयजल को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए जल का अधिकार कानून बनायेंगे।
- हर घर को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

न्यूनतम आय का अधिकार

- कांग्रेस सरकार प्रदेश के प्रत्येक घर के 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है और रोजगार न मिलने पर सामाजिक सुरक्षा के तहत न्यूनतम आय उपलब्ध कराने के लिए कानून बनाने की और कदम बढ़ायेगी।

गरीब एवं मध्यम आय वर्ग के साथ न्याय

- गरीब एवं मध्यम आय वर्ग के साथ अन्याय न हो, इसके लिए व्यवस्था में सुधार करेंगे।
- इस वर्ग की समस्याओं के निराकरण हेतु 3 सदस्यीय आयोग का गठन करेंगे।
- युवाओं को विदेश अध्ययन की सुविधा देंगे व यूथ हॉस्टल बनायेंगे।
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा देंगे।
- आय प्रमाण-पत्र की अवधि व सीमा बढ़ायेंगे।
- प्रथम आवास खरीदने पर पंजीयन शुल्क में रियायत का प्रावधान करेंगे।
- गरीबी रेखा का सर्वे कराकर, वास्तविक एवं पात्र परिवारों को ही जोड़ेंगे।
- पात्र गरीबों को राशन किट देंगे।

बढ़ाइये हाथ फिर कमलनाथ